भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2436
10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

ईवी के लिए राजसहायता

2436. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को निजी कारों सहित ई-वाहनों के लिए राजसहायता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;?

(ग) पंजाब में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रेपिंग के लिए कोई नीति बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार पुराने वाहनों को ई-वाहनों में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

भारी उद्योग राज्यमंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : जी नहीं। ई-वाहनों के लिए राज्य सरकारों को राजसहायता नहीं दी जाती। किन्तु, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। भारी उद्योग मंत्रालय ने पंजाब सहित अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित स्कीमों तैयार की हैं-

- i. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II : सरकार ने इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 11,500 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से तैयार किया था। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया, ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया।
- ii. भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो) : सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एटीटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता संवर्धन हेतु भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक

- उद्योग के लिए इस स्कीम को 25,938 करोड़ रूपए के बजट परिव्यय के साथ 23 सितंबर,2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन वाले एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है।
- iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) संबंधी पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 12 मई,2021 को 18,100 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी की 50 गीगावाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करना है।
- iv. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवाॅल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम :** सरकार ने 10,900 करोड़ रूपए परिव्यय वाली इस स्कीम को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया। इस दो-वर्षीय स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया वाहनों, ई-तिपहिया वाहनों, ई-ट्रकों, ई-बसों, ई-एम्बुलेंस तथा इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए सहायता प्रदान करना और परीक्षण एजेंसियों का स्तरोन्नयन करना है।
- v. **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम :** 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रूपए है और इसका लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता प्रदान करना है। स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) से भुगतान में विलंब की स्थिति में ई-बस प्रचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।
- vi. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम :** भारत में इलेक्ट्रिक कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रूपए का निवेश करना होता है और तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन तथा पांचवे वर्ष के अंत तक 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होता है।

अन्य मंत्रालय के उपायों में निम्नांकित पहले शामिल हैं-

- i. विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के लिए **गाइडलाइन्स फॉर इन्सटॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर-2024** नाम से 17 सितंबर,2024 को दिशानिर्देश और मानक जारी किया है। इन संशोधित दिशानिर्देशों में देश में सुसंबद्ध और अंतर-प्रचालनीय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग

अवसंरचना नेटवर्क सृजित करने संबंधी मानक और नवाचार दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली कनेक्शन भी आसान हुए हैं।

- ii. वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
- iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।
- iv. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आदर्श भवन बाइ-लॉज को संशोधित कर निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशनों को शामिल करना अनिवार्य बना दिया है।

(घ) और (ङ) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रेपिंग नीति तैयार की है जिसमें देशभर के पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप में हटाने का पारितंत्र सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देने/हटाने करने की व्यवस्था शामिल है।

(च) और (छ) : ऐसा कोई प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। किंतु, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष की सहायता के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं।